Minimum Wages to beedi workers

*589. SHRI NANDI YELLAIAH: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Government monitors in every State the mandatory condition of paying minimum wages to beedi workers in the country and compulsory deduction thosefrom for deposit in their Provident Fund Scheme;

(b) if so, the details of checks exercised, so far;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether Government monitors compulsory payment of minimum wages and compulsory deductions towards Provident Fund Scheme in respect of beedi workers who in large numbers work in their residence outside beedi factories;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI K. CHANDRASEKHAR RAO): (a) to (f) A statement is laid on the table of the House.

Statement

The State Governments are the appropriate authority for ensuring the payment of minimum wages to beedi workers under the Minimum Wages Act, 1948. Accordingly, monitoring of the implementation of minimum wages in respect of beedi workers is done by the respective State Governments.

Deduction of employees' contribution and remittance thereof along with the employers' share towards Provident Fund is a statutory requirement for all establishments (including Beedi Establishments) under the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952. As on 31.3.2004, 17.96 lakh beedi workers in respect of 4158 establishments were covered under the Act. The State-wise wise break up is given in the Statement-I (*see* below).

A special drive has also been launched by Employees' Provident Fund Organization for coverage of beedi workers as a result of which 47,087 beedi workers have been enrolled in respect of 270 establishments during January-March, 2005.

Compliance of the covered establishments is regularly monitored through a computer software namely, Computerised Compliance Tracking System (CCTS). In case of detection of default, appropriate action for assessment of dues and recovery thereof is taken by the Employees' Provident Fund Organization.

Statement-I

Membership in Beedi Establishments-position as on 31.3.2004

	Establishments			Members		
Region	Exempted	Un-Exempted	Total	Exempted	Un-Exempted	Total
Andhra Pradesh	0	393	393	0	423474	423474
West Bengal	0	216	216	0	366946	366946
Tamil Nadu	0	2083	2083	0	298975	298975
Karnataka	0	276	276	0	252661	252661
Madhya Pradesh	0	256	256	0	150807	150807
Maharashtra	2	150	152	4592	87313	91905
Kerala	0	126	126	0	61030	61030
Orissa	0	181	181	0	58845	58845
Jharkhand	0	38	38	0	29780	29780
Bihar	0	27	27	0	28246	28246
Rajasthan	0	133	133	0	13668	13668
Uttar Pradesh	0	153	153	0	9415	9415
Chhattisgarh	0	43	43	0	8250	8250
North Eastern Region	0	21	21	0	1254	1254
Gujarat	0	60	60	0	1102	1102
Delhi	0	0	0	0	0	0
Goa	0	0	0	0	0	0
Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
Haryana	0	0	0	0	0	0
Punjab	0	0	0	0	0	0
Uttaranchal	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	4156	4158	4592	1791766	1796358

श्री नंदी येल्लैया: माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे श्रम मंत्री ने बीड़ी वर्कर्स के बारे में जो आँकड़ा पेश किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि Minimum wages in respect of beedi workers is fixed by the respective State Governments, इसका उन्होंने जिक्र किया। शायद इन्हें भी मालूम है, क्योंकि वे भी एक रिमोट एरिया से आते हैं ... (**व्यवधान**). .. मैं भी वहीं से आता हूँ, सर, बीड़ी वर्कर्स के बारे में इन्होंने जो आँकड़ा दिया है, फैक्टरी में जो काम करते हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे बीड़ी वर्कर्स हैं, जो घरों में काम करने वाले हैं ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। क्वैश्चन पूछ लीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: सर, इसका क्वैश्चन से ताल्लुक है, क्वैश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें घरों में काम करने वाले आउटसाइडर्स बीड़ी वर्कर्स का ब्यौरा नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि यह राज्य सरकार का काम है, लेकिन केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। घरों में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, क्या लेबर इंस्पेक्टर उनके पास जाते हैं, क्या उनके पास इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा है? मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूँ।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir , the minimum wages for the beedi workers are fixed by the respective State Governments. So far, in the country, minimum wages for beedi workers are fixed by 18 States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh. Minimum wages are fixed by the respective State Governments according to their local conditions. The Government of India also monitors. We have a Minimum Wages Board at the national level. They go round the country; they review matters, and wherever some suggestions and support are required, they are extending. माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जो एक-एक, दो-दो लोग घर में बैठ कर बीड़ी बनाते हैं, उनका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। सर, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। मिनिमम वेज लागू करने के लिए कुछ नियम होते हैं ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इन्हें बोलने दीजिए।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: जो वाइड-स्प्रेड होते हैं, उनके लिए सरकार जरूर प्रयास करती है, लेकिन 100% इंश्योर करना मुश्किल होता है, यह सभी को मालूम है, सब को इसकी जानकारी है। सरकार प्रयास करती रहती है।

श्री नंदी येल्लैया: सर, हमारी सरकार से ... (**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, मंत्री महोदय ने ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिए, बीच में नहीं बोलने दूंगा। आप बैठिए, वह बोल रहे हैं। ... (**व्यवधान**)... मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए, इसमें मैं क्या करूं?

श्री नंदी येल्लैया: सर, अभी हमारे श्रम मंत्री महोदय ने कहा कि मुश्किल है, कौनसी मुश्किल है, क्योंकि बीड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाली जो majority है, वह गरीब ladies की है। ये महाराष्ट्र में नंबर 1 हैं, नंबर 2 निजामाबाद में हैं जोकि मेडक डिस्ट्रिक्ट में हैं। मैं श्रम मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले या मकान के काम में लगे मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के तहत, जैसे वीकली हॉली डे मिलता है, सालाना लीव मिलती है, क्या इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को यह सुविधा दी गयी है?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, मैं इसके बारे में थोड़ासा खुलासा करना चाहूंगा। हमारे देश में 1492 ऐसे scheduled employments हैं जिन के लिए मिनिमम वेजेज फिक्स कराए गए हैं। इन 1492 में से 1445 को राज्यों की सरकारें implement करती हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, important क्वैश्चन यह है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और फैक्ट्री के बाहर काम करने वाले मजदूर ... (**व्यवधान**)...

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, मैं वही कहने जा रहा हूं।

श्री नंदी येल्लैया: सर, मंत्री जी ने मिनिमम वेजेज का जिक्र नहीं किया। उन्हें कितना वेजेज मिलता है, उसका जिक्र नहीं किया जोकि बहुत important है।

श्री सभापति: बोलने दीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दिलवाऊंगा। ... (**व्यवधान**)... बैठिए।

श्री नंदी येल्लैया: सर, वेजेज का सवाल फर्स्ट है। उसको आप कितना वेजेज दे रहे हैं, क्या 55 रुपए दे रहे हैं, हजार पर कितना दे रहे हैं, छोटे साइज को कितना दे रहे हैं, बड़े साइज वाले को कितना दे रहे हैं, इसका आपके स्टेटमेंट में कोई जिक्र ही नहीं है। मिनिमम वेजेज बताइए।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, minimum wages in the country are fixed for 1492 Scheduled employments जिनमें से बीड़ी भी एक scheduled employment है। इसे लागू करना राज्य सरकारों की विधि है, राज्यों की सरकार उसको implement करती है। इससे लिए राज्यों की सरकारें ऐसा प्रयास करती हैं कि हजार बीड़ी बनाने वालों को मिनिमम वेजेज के तहत इतनी रकम मिलनी चाहिए। ये राज्यों की सरकारें respective management से बात करके तय करती हैं। मेरे पास पूरी information है: Andhra Pradesh - Rs. 85 per day फिक्स किया गया है; Assam- Rs. 60 per thousand beedi फिक्स किया गया है; Arunachal Pradesh- Rs. 39 87 for first

area, and for second area, Rs. 42.11 फिक्स किया गया है; Bihar- Rs. 64.62 per thousand beedis फिक्स किया गया है; Chhattisgarh- Rs. 66.60 per day फिक्स किया गया है; Dadar and Nagar Haveli - Rs. 84 per day इस प्रकार से राज्यों की सरकारें मिनिमम वेजेज देती हैं। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। ... (व्यवधान)... बैठ जाइए।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, गुजरात में 84 रु॰ 40 पैसा per thousand beedis; कर्नाटक में 65 रु॰ 06 पैसा per day फिक्स किया गया है, केरल में 84 रु॰ 20 पैसा बीड़ी एंड सिगार इंडस्ट्री में per thousand beedi फिक्स किया गया है। मध्य प्रदेश में 77 रु. 30 पैसा per day फिक्स किया गया है, महाराष्ट्र ... (व्यवधान)... आप सुनिए, मुझे complete करने दीजिए।

श्री सभापति: Please don't disturb him. यह गलत बात है।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, महाराष्ट्र में दो एरिया decide किए गए हैं। एक जगह 49 रु॰ 50 पैसा और दूसरी जगह 57 रु॰ 50 पैसा per thousand beedis तय किए गए हैं।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: इस प्रकार से हर राज्य में राशि वहां की सिचुएशन के मुताबिक राज्यों की सरकारों द्वारा फिक्स की गयी है।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, right from the success in space which we lauded, now we come to the ground realities, the *beedi* workers. Now, that *mushkil kaam* could be resolved but this *mushkil kaam* is something which we are not in a position to resolve. This is an issue on which, I think, everyone is equally concerned.

My first clarification is that some figures are being given, as the figure of 85 is given. I have gone to five places where these beautiful figures are there, but actually they are being paid 30 to 35 rupees. Here the question is of implementation. Sir, the point that I am going to raise here is that specifically you have a monitoring of the Minimum Wage but you also have the monitoring system also as per the employees provident fund Act, 1952. This is a Central legislation and you are monitoring it. I am telling you specific figures with respect to Jharkhand State where I have to visit next week. In Jharkhand State, Pakur, Rajmahal, Sahibganj areas...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It wil be very difficult for him to tell about Jharkhand...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I am telling these are just the areas where you find violation of both. I would like to know whether you have violation of both the social security Employees Provident Fund Scheme, as well as, minimum wage. Would you kindly have such samples in different States and have a monitoring in all these areas? And, then, would you give a feedback to this House in the next Session as to what exactly is being paid and what are the reasons for the Employees Provident Fund Scheme and the social security not being implemented?...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Hon. Minister.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am telling about Jharkhand. This issue relates to the areas, Pakur, Rajmahal as well as Sahibganj. There is tremendous unrest and it may erupt any time. I would like to know whether you would have a sample survey and come out with actual position ...(*Interruptions*)... Don't wait for the Arjun Sen Gupta Commission's Report for that ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ठीक है। Let him reply.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: I assure the hon. Member that I will send a special team to the areas that he has mentioned and see that necessary action is taken against them.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Identify some areas in the whole of the country ...(*Interruptions*)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Please bear with me. मिनिमम वेजेज दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें भी प्रयास करती हैं, सर। मुझे उत्तर देने दीजिए। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप पूरा समय लीजिए। आज तो बीड़ी वालों का दिन हो गया।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: The Government and the central inspector, the Chief Labour Commissioner of the country and his staff conduct regular periodical inspections to ensure that minimum wages are paid to the *beedi* workers and other workers also.

Sir, the number of inspections made in the Central sphere during the year 2003-04 is 15,212, the number of irregularities rectified is 1.87 lakhs, the number of claims filed is 3,956, and the number of persons prosecuted in the Central sphere is 5,267. We have received reports from all the States. Accordingly, the number of inspections conducted by all the State Labour Departments in the country is 55.44 lakhs, 2 lakh irregularities have been detected, 3.16 lakh irregularities have been rectified, 0.54 lakhs claims filed, and, 0.19 lakhs claims settled, and, Sir, the number of persons prosecuted ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, लेबर कमिश्नर मालिकों से जाकर बात करते हैं। I am charging here right now that the Chief Labour Commissioner, they send their Labour officials, they talk to the *malik*, they never talk to the unions.

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।...(**व्यवधान**)... बैठिये।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will you see that the Chief Labour Commissioner, or, the Labour officials don't talk to the *maliks* only but they talk to the unions also?

MR. CHAIRMAN: Let him finish ...(*Interruptions*)... Mr. Mukherjee, let him finish.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, I am trying to inform the House as to what the Government is doing. If the Members are having any specific allegations ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: छोड़िए, उसे छोड़िए।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Please hear me. ...(*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: Sir, half-an-hour discussion ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप लिखकर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Please hear me. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप लिखकर दीजिए, लिखकर। ...(**व्यवधान**)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, if you have any specific allegation in any specific area, I request the hon. Member to bring it to my notice and the Government will take prompt action on that.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, wherever it is needed, you don't go and wherever it is not needed, you go like Air India ...(*Interruptions*) ..

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

SHRI K CHANDRA SEKHAR RAO: What Air India? What Air India, Sir. No, it cannot be alleged like that, Sir. You have to protect me, Sir. I am sorry.

MR. CHAIRMAN: What did he say?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: You have to protect me, Sir.

MR. CHAIRMAN: What did he say?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: What Air India ...(*Interruptions*)...If they want to say anything, I am prepared to answer them ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: He must be aware that the issue has already been raised ...(*Interruptions*)... The issue was already raised, ...(*Interruptions*)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO. Even the other day they were making allegations against me. .. (*Interruptions*)... It is unfair, Sir. You have to protect me, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, what did he say? ...(*Interruptions*)... यह मुझे दिखाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: It was already raised in the House, ...(*Interruptions*)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, this way they cannot allege ...(*Interruptions*)...

श्री नीलोत्पल बसु: यह बात हाउस में उठ चुकी है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं, वह मुझे दिखाइए, जो लिखा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, वह तो यहां के प्रोसीडिंग में है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Last question ...(*Interruptions*)... Shri Fali Nariman.

SHRI FALI S. NARIMAN: Sir, I would ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: The labour Minister ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप कुछ बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप हर चीज में खड़े हो जाते हैं। जैसे बीड़ी में भी, सिगरेट में भी, सिनेमा में भी। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमना देवी बारुपाल: सभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... यह नहीं लिखा जाता ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमना देवी बारुपाल: सभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... फिर भी बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... इनके बाद मैं आपको चांस दूंगा। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... नहीं, यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... Noting will go on record ...(*Interruption*)... Nothing will go on record. ...(**व्यवधान**)... अगर आप बोलेंगे तो यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप बोलते रहिए, यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... यह राजस्थान की महिला है, आसानी से नहीं बैठेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपकी भी यही हालत है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI FALI S. NARIMAN: Sir, my question to the hon. Minister is, he is perfectly aware that agricultural labourers form the largest possible section of employment in this country. And, since India is a Union of States, I would request all the hon. Ministers to please remember, because I view with dismay, some of the pattern of answers that have been given to this House, namely, "this is the business of the States, this is the business of the States". You feel, Sir, that if this is the business of the States, we are the Council of States. We are entitled to know with regard to how the monitoring is conducted in respect of all the Central laws. Now, agricultural labourers are also subjected to the Central law. How is

it that the hon. Minister, once he has information, I have no doubt, what steps has he taken to establish responsibility?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, I was very clearly telling the reports received from the respective State Governments. Sir, we are a federal system. We have given powers in the Concurrent List to States also. We allow the State Governments to function in this country. We trust in our State Governments. The reports, whatever is officially received from the respective State Governments, I will try to submit to the hon. Members. And, another thing...(*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY: Reports are prepared by the Standing Committee ...(*Interruptions*) You go through the report and take ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Wait for one minute. ...(*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY: You have not gone through the reports which are prepared by the Standing Committee on *Bidis*. ...(*Interruptions*). Nothing is being done by the Central Ministry. ...(*Interruptions*)

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, whatever has been done by the Government, I will try to submit, through you, Sir. The information which I have with me, I will try to put...(*Interruptions*). Anything specific with the hon. Members ...(*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY: You go through the report of the Standing Committee ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please, take your seat. ...(*Interruptions*)

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Mr. Chairman, Sir, if anybody wants anything specific, the Government will take proper action.

श्रीमती जमना देवी बारुपाल: सभापति महोदय, आज यह सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी बैठे हैं। हम सब सांसद लोग ढिंढोरा पीट-पीट कर गीत गाते हैं कि दलितों के लिए कुछ किया जाए, दलित महिलाओं के लिए कुछ किया जाए, यह किया जाए, वह किया जाए और जब हम यहां बोलते हैं, तो मैं जो बोलती हूं, *मैंने कल यह बोला था कि मेरे देश में ...(**व्यवधान**)... आप लोग क्यों हंसते हो? मैं सप्लीमेंटरी यह पूछ रही हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सप्लीमेंटरी बहुत अच्छा पूछ रही हैं, आप। ...(**व्यवधान**)...

*Not recorded.

श्रीमती जमना देवी बारुपाल: सर, आज देश की बढ़ती हुई आबादी को देखकर जो इंटरव्यू देने जाते हैं आई.ए.एस. का, आई.पी.एस. का, कलेक्टर का, जो भी, तो उस वक्त उनको यह हक देना चाहिए और उनको यह मौका देना चाहिए उन लोगों के साथ में, कि वे अच्छी तरह से अपना साक्षात्कार दे सकें। *मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: श्री दत्ता मेघे।

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, मेरा क्वैश्चन इतना ही है कि जो लोग घर में बीड़ी बनाते हैं, वे ज्यादा लोग हैं। ये बीड़ी वाले सबसे ज्यादा इन्कम टैक्स देते हैं, लेकिन घर में बनाकर। आपके जो रूल्स हैं, घर में जो बीड़ी बनाते हैं उनके लिए, क्या आप इन्हें कड़ाई से लागू करेंगे?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सभापति जी, ऐसा है कि पहले तो एक ही जगह ये लोग फैक्टरी में बीड़ी बनाते थे, फिर धीरे-धीरे अपने घर में भी बनाना शुरू कर दिया। I assure the Hon'ble member, घर में भी जो बीड़ी बनाते हैं, उनको भी मिनिमम वेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, यह ध्यान रखिए कि समस्या बहुत बड़ी है। बीड़ी जगह-जगह बनती है, मजदूरों को भी राहत मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलती है। इसके ऊपर आप थोड़ा विचार करें। Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Opening of Post Office in Sant Nagar, Delhi

*582. SHRI BALAVANT *ALIAS* BAL APTE: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that residents of Sant Nagar, Delhi-84, which is a densely populated colony, are demanding since long opening of a Departmental sub Post Office;

(b) if so, the reasons for not taking steps to open a Departmental sub Post Office to cater to the needs of the people of said area; and

(c) by when the demand would be met?

---

*Not recorded.